साप्ताहिक

डाक पंजीयनः म.प्र./भोपाल/4-479/2019-21

RNI-MPHIN/2015/72544

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार, 22 मार्च 2021, वर्ष-6, अंक-51

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 8 रुपए

सीएम शिवराज सिंह बोले

जल्द सर्वे कर देंगे मुआवजा राशि

- इंदौर-भोपाल और उज्जैन में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि
- कई जगह बिछी बर्फ की चादर, खरगोन में भी फसलें हो गईं चौपट
- पीथमपुर, महू और नीमच, धार के गांवों में बारिश के साथ गिरे ओले
- बड़ौनी के गांवों में गिरे ओले, किसान बोले-फसल बर्बाद
- आंधी-बारिश के साथ गिरे ओले, फसलों को भारी नुकसान
- बुरहानपुर, शाजापुर जिले में आंधी-बारिश व ओले गिरे
- पककर खड़ी व खलिहानों में कटी गेहूं की फसल बर्बाद
- बुरहानपुर में चने बराबर गिरे ओले, केला भी चौपट
- जिलों में लहुसन, प्याज सहित अन्य फसलें भी प्रभावित हुईं

उम्मीदों पर ओलावृष्टि

सरकार ओला पीड़ित किसानों को देगी 5500 करोड़ की राहत

संवाददाता, भोपाल

मध्यप्रदेश में बेमौसम बारिश और ओले गिरने से गेहूं, चना और प्याज के साथ ही सब्जियों की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। किसानों की गेहूं की फसल या तो खेतों में कटने के लिए खड़ी थी या फिर कहीं पर आधी कटाई होकर खेत में रखी थी। ओलों की वजह से हुई फसलों की बर्बादी ने किसानों की आंख में आंसू ला दिए है। वहीं बारिश-ओलों से प्रभावित किसानों के लिए राहत का पिटारा खोलते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 5500 करोड़ की मंजूरी दी है। जल्द ही किसानों का सर्वे कर राहत राशि देने का काम शुरू हो जाएगा। उधर, केंद्रीय योजनाओं के संचालन के लिए विभागों को तय खर्च सीमा में छूट प्रदान कर दी गई है। प्रदेश के किसानों को ओला-बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदा की स्थिति में राहत देने और प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ दिलाने के लिए सरकार ने बजट सत्र में पारित किए गए अनुपूरक बजट में 5500 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। अलग-अलग मदों में यह राशि किसानों के हित से जुड़ी है जिसे कैबिनेट की मंजूरी के बाद अनुपूरक बजट से भी मंजूरी मिल गई है। सरकार द्वारा बजट में किए गए प्रावधानों के चलते पिछले कुछ दिनों में हुई ओलावृष्टि और फसल आड़ी तिरछी होने की स्थिति में किसानों का सर्वे करके राहत राशि देने का काम किया जाएगा।

किसान चिंता न करें, सभी को मिलेगा मुआवजा

प्रदेश के जिन हिस्सों में ओलावृष्टि एवं बारिश से फसलों को नुकसान हुआ है, वहां के किसान चिंता न करें। सर्वे के निर्देश दे दिए गए हैं। शीघ्र ही यह प्रारंभ हो जाएगा। किसानों को फसलों के नुकसान का समुचित मुआवजा दिया जाएगा।

शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री

प्रदेश के जिन हिस्सों में ओलावृष्टि एवं बारिश से फसलों को नुकसान हुआ है, वहां के किसान परेशान न हों। सर्वे शुरू हो चुका है। सब को राहत दी जाएगी। प्रमुख सचिव, कृषि अजीत केसरी को हितग्राही मूलक प्रोजेक्ट तैयार करने के निर्देश दिए। किसानों को अधिकतम लाभ दिलाया जाएगा।

कमल पटेल, कृषि मंत्री

इंदौर सहित संभाग के सभी जिलों में हुई ओलावृष्टि से हुए नुकसान पर तत्काल सर्वे शुरू किया जाएगा। देपालपुर, हातोद, सांवेर सहित अन्य क्षेत्रों में जहां कहीं भी नुकसान हुआ है, वहां राजस्व प्रशासन सर्वे करे और राजस्व पुस्तक परिपत्र के अनुसार प्रकरण तैयार करें।

तुलसी सिलावट, मंत्री

किसानों को नुकसान हुआ है। प्रशासन व सरकार से मांग की जा रही है कि जल्द ही सर्वे करवाकर मुआवजा दिलाएं। होली जैसा प्रमुख त्योहार करीब है। इसके चलते किसानों को गेहूं की फसल से ही आस रहती है।

आनंद ठाकुर, भारतीय किसान संघ

खंडवा के 40 गांवों में फसलें बर्बाद

खंडवा जिले के पंधाना ब्लाक के ग्रामीण क्षेत्रों में 25 मिनट तक हुई ओलावृष्टि ने 40 गांवों में फसलों को बर्बाद कर दिया। पंधाना तहसीलदार स्वाति मीणा ने बताया कि 12 पटवारी हल्कों का निरीक्षण करेंगे। इसके लिए राजस्व विभाग, उद्यानिकी विभाग व कृषि विभाग की संयुक्त टीम यह आकलन करेगी। इसके बाद किसानों को राहत दी जाएगी।

जागत गांव हमार की खबर पर एमपी विधानसभा में लगी मुहर

सरकार ने स्वीकाराः पीएम किसान सम्मान निधि में हुआ फर्जीवाड़ा

विशेष संवाददाता, भोपाल

पहले केंद्र सरकार ने लोकसभा में कबूल किया कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में 32.91 लाख अपात्र किसानों को 2,327 करोड़ का भुगतान कर दिया गया। इससे केंद्र को 2,327 करोड़ का चूना लग गया। हालांकि, ये पहली बार नहीं है, जब सरकार ने इस योजना के तहत गड़बड़ी की बात मानी है। अब मप्र सरकार ने भी विधानसभा के बजट सत्र के दौरान स्वीकार किया है कि उक्त योजना में फर्जीवाड़ा हुआ है। गौरतलब है कि '**जागत गांव हमार**' ने अपने 15 फरवरी के अंक में 'अपात्र हो गए आत्मनिर्भर' शीर्षक से प्रमुखता के साथ खबर प्रकाशित की थी। जिसमें यह भी बताया गया था कि पीएम किसान सम्मान निधि में फर्जीवाड़े में तमिलनाडु पहले, पंजाब दूसरे और मप्र छठे नंबर पर है।

जागत गांव हमार

अपात्र हो गए 'आत्मनिर्भर'

- 1,70,596 अपात्र किसानों को नोटिस
- सिर्फ 9,960 ने लौटाई सम्मान राशि
- कांग्रेस विधायक हर्ष यादव ने विधानसभा में पूछा था सवाल

दस हजार अपात्रों ने लौटाई राशिः मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 1 लाख 70 हजार 596 अपात्र किसानों के खाते में राशि पहुंची है। राज्य सरकार ने अपात्र किसानों को राशि लौटाने का नोटिस भेजा है। इसमें से अभी तक सिर्फ 9,960 किसानों ने राशि लौटाई है। केंद्र सरकार की इस योजना में फर्जीवाड़ा होने के आंकड़े विधानसभा में दिए। इसको लेकर कांग्रेस विधायक हर्ष यादव ने सवाल लगाया था, जिसका लिखित जवाब राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने दिया। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि अपात्र किसानों के खातों में कितनी राशि ट्रांसफर हो चुकी है।

कांग्रेस विधायक ने पूछा था कि एक जनवरी 2021 की स्थिति में प्रदेश में कितने किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अपात्र मानते हुए राशि वापस लेने के लिए नोटिस जारी किए गए। इनमें से कितने किसानों ने अब तक राशि लौटाई। राजस्व मंत्री के जवाब में बताया कि प्रदेश में सबसे ज्यादा नोटिस उज्जैन के 9323 अपात्र किसानों को दिए गए। इसमें से 163 किसानों ने राशि लौटाई है। इसी तरह सीहोर-छिंदवाड़ा में 8-8 हजार से अधिक अपात्र चिन्हित किए गए हैं। गौरतलब है कि सीहोर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और छिंदवाड़ा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का गृह जिला है।

किसानों से धोखाधड़ी पर व्यापारी को 5 साल की सजा

संवाददाता, भोपाल

किसानों से धोखाधड़ी करने वाले व्यापारी को हरदा जिला न्यायालय ने पौने तीन साल चली सुनवाई के बाद 5 साल के कारावास और दो लाख के अर्थदंड से दंडित किया है। व्यापारी ने किसानों से उनकी उपज लेने के बाद बिना पैसे दिये भाग गया था। मूलतः होशंगाबाद जिले के रहने वाले व्यापारी ओमप्रकाश सोनी ने टेमागांव उसकल्ली के 22 किसानों से चना खरीदा था, लेकिन लेकर उन्हें उपज का भुगतान नहीं किया था। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने व्यापारी को 5 साल की सजा और 2 लाख के जुर्माने से दंडित किया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर 2 साल का कारावास और भुगतना होगा।

- पौने तीन साल चली सुनवाई के बाद दो लाख जुर्माना भी
- हरदा जिले के 22 किसानों से चना लेकर सिवनी में बेच दिया था

22 किसानों का पैसा नहीं दिया: हरदा जिला कोर्ट के शासकीय अतिरिक्त लोक अभियोजक प्रवीण सोनी ने बताया कि हरदा जिले के टेमागांव में रहने वाले व्यापारी ओम प्रकाश सोनी ने 2018 में 23 किसानों से 855.70 क्विंटल चना खरीदा था। इसका 37 लाख 87 हजार 480 रुपए भुगतान करना था, लेकिन व्यापारी ने 1 व्यापारी का भुगतान किया और बाकी बचे 22 व्यापारियों के 27 लाख 37 हजार 880 रुपए नहीं दिए। इसके बाद पीड़ित किसानों ने 25 अप्रैल 2018 को रहटगांव थाने में व्यापारी खिलाफ केस दर्ज कराया था।

फसल दूसरे व्यापारी को बेचीः अतिरिक्त लोक अभियोजक ने कहा कि व्यापारी ने टेमागांव में एक कमरा किराए से लिया था। व्यापारी ने हरदा जिले के 22 किसानों से चना लेकर उसे सिवनी बनापुरा के व्यापारी को बेच दिया था, लेकिन पैसा किसानों को नहीं दिया। लाखों रुपए की राशि लेकर व्यापारी रातोंरात चम्पत हो गया था।

■ जिम्मेदारों की अनदेखी से न अमला, न उपकरण

एमपी में शो-पीस बनीं मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं

संवाददाता, भोपाल

जहां एक ओर मध्यदेश में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के दावे किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर किसानों की मदद के लिए शुरू की गई मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं शो-पीस बन गई हैं। अनदेखी का आलम यह है कि प्रयोगशालाओं में न तो उपकरण हैं और न ही जरुरत के हिसाब से अमला है। जब सरकार ने इनकी स्थापना का फैसला किया था, तब इनको लेकर बड़े जोर-शोर से प्रचार-प्रसार कर ढोल पीटे गए थे। अब इन प्रयोगशालाओं को लेकर सरकार कठघरे में खड़ी नजर आ रही है। किसानों द्वारा इनको लेकर अब उपयोगिता और औचित्य पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल, प्रदेश में किसानों को अच्छी उपज मिले इसके लिए इन प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई थी। किस जगह की मिट्टी में कौन से पोषक तत्व है और कौन से कम हैं इनका पता यहां प्रयोगशालाओं में किया जाना था। इसकी जानकारी मिलने के बाद मिट्टी का उपचार कर उसे बेहतर बनाकर किसान अच्छी फसल ले सकें। यही नहीं, इससे यह भी पता लगाया जाना था कि किस क्षेत्र में कौन सी फसल ली जाए। इसकी वजह है प्रदेश का क्षेत्रफल अलग होने की वजह से अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग तरह की फसलें उगाई जाती हैं। क्षेत्र के हिसाब से जमीन की प्रकृति भी अलग होती है। इस मिट्टी परीक्षण से किसानों को यह बताया जाना था कि वे कौन सी फसल लें। शिवराज सरकार द्वारा सभी तहसील मुख्यालयों पर इस तरह की प्रयोगशाला स्थापित करने की योजना तैयार की गई थी। इसके तहत एक साथ 265 नई प्रयोगशालाओं की स्थापना की जानी थी। खास बात यह है कि इनमें से 261 तैयार भी हो चुकी हैं। इन पर सरकार द्वारा 111 करोड़ की राशि खर्च भी कर दी गई है। इसके बाद भी इनका उपयोग नहीं हो पा रहा है।

50 प्रयोगशालाएं संचालित

प्रदेश में फिलहाल 50 प्रयोगशालाएं ही काम कर रही हैं। इनमें भी अधिकांश में सुविधाओं का अभाव है। इस वजह से उनसे भी किसानों को समय पर रिपोर्ट नहीं मिल पाती है। ऐसे में नई प्रयोगशालाओं को लेकर भी किसानों में संशय होना स्वभाविक है।

मशीनें खरीदी पर दी नहीं

अनदेखी का आलम यह है कि प्रयोगशालाओं की जरूरत के हिसाब से प्रशिक्षित अमले का इंतजाम भी नहीं है। इसकी वजह से मिट्टी का परीक्षण ही नहीं हो पा रहा है। यही नहीं, इसके लिए जरुरी उपकरणों की भी व्यवस्था नहीं की गई है। फिलहाल मशीनों के नाम पर सिर्फ अब तक केवल एएएस मशीनों को तो खरीद लिया गया है , लेकिन उन्हें अब तक प्रयोगशालाओं में ही नहीं भेजा गया है।

करना पड़ सकता इंतजार

प्रयोगशालाओं के काम की गति को देखते हुए माना जा रहा है कि राज्य सरकार अगर इनके मामले में तेजी से भी काम करे तो कम से कम छह माह उनमें अमले से लेकर मशीनों तक की व्यवस्था में लग जाएंगे। यही नहीं, सरकार पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रही है, जिसकी वजह से फिलहाल इन प्रयोगशालाओं के लिए उपकरण का इंतजाम होना मुश्किल दिख रहा है। यदि उपकरणों का इंतजाम भी कर लिया गया तो फिर अमले का इंतजाम करना बड़ी चुनौती रहेगी। इस साल तो किसानों को नई मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं का फायदा मिलना मुश्किल है।

दतिया में गन्ना उत्पादक किसानों से बोले गृह मंत्री

शक्कर ने दिलाई डबरा को नई पहचान, अन्नदाता कम लागत में अधिक लाभ लें

संवाददाता, भोपाल

परम्परागत खेती के साथ बदले वातावरण में कृषि में आधुनिक एवं उन्नत तकनीकी का उपयोग कर किसान कम लागत में अधिक लाभ लें। दतिया के किसान मेहनत, लगन, वैज्ञानिकों की सलाह एवं शासन की योजनाओं का लाभ लेकर उन्नत तकनीकी का उपयोग कर कम लागत में अधिक उत्पादन ले रहे हैं। दुनिया में हर क्षेत्र में क्रांति आई है। कृषि का क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा है। किसानों को बदली हुई परिस्थिति अनुसार खेती-किसानी के तौर तरीकों में बदलाव लाना जरूरी हैं। कृषि के क्षेत्र में उन्नत एवं आधुनिक तकनीकी का उपयोग कर अधिक उत्पादन लेने का प्रयास कर आने वाली पीढ़ी को खुशहाल बनाना है। यह बात प्रदेश के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत वृंदावन धाम में आयोजित गन्ना उत्पादक कृषकों की कार्यशाला और वैज्ञानिक परिचर्चा के दौरान कही। गृह मंत्री ने कहा कि डबरा की सुगर फैक्ट्री में शक्कर निर्माण में जिले के गन्ना उत्पादक किसानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। किसानों के द्वारा पैदा किए गए गन्ने के कारण ही डबरा को शक्कर के रूप में पहचान मिली है।

गुड़ को विशेष पहचान दिलाएं

मंत्री ने कहा कि दतिया जिले के गोराघाट क्षेत्र में उत्पादित गन्ने से मेरठ से भी अच्छा गुड़ बनाया जा रहा है। गोराघाट के गुड़ को पहचान दिलाने के लिए किसान उन्नत किस्म का गन्ना पैदा कर उन्नत तकनीकी का उपयोग कर बेहतर गुणवत्ता का गुड निर्माण करें। भारतीय गन्ना अनुसंधान केन्द्र लखनऊ के वैज्ञानिकों द्वारा गन्ना उत्पादन के संबंध में जो तकनीकी मार्गदर्शन एवं गन्ने की उन्नत किस्में बोने की सलाह अनुसार गन्ने की फसल लें। गन्ने से बनने वाले सीरे का उपयोग ईंधन निर्माण में भी किया जा रहा है। गन्ने की खोई का भी उपयोग बिजली उत्पादन में लिया जा रहा है।

कुटीर उद्योग स्थापित करें

किसान आलू, टमाटर पर केन्द्रित चिप्स एवं सॉस के गांव में कुटीर उद्योग स्थापित कर आय के साधन बढ़ा सकते हैं। गौ-माता का गोबर भी काफी उपयोगी है। गाय के गोबर से पेंट का निर्माण किया जा रहा है। भोपाल में मुक्तिधामों में अंतिम संस्कार में गोबर से बनी लकड़ी का उपयोग किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश में नई व्यवस्था लागू

किसानों को नहीं होगा खाद संकट

संवाददाता, भोपाल

मध्य प्रदेश में बीते कुछ सालों से खरीफ और रबी सीजन की फसलों के समय खड़े होने वाले खाद संकट को देखते हुए इस बार खाद भंडारण की नई व्यवस्था लागू की जा रही है। इस नई व्यवस्था को लेकर शिवराज सरकार द्वारा निर्णय लिया जा चुका है। नई व्यवस्था के तहत अब प्राथमिक साख सहकारी समितियों को उनके द्वारा की जाने वाली बिक्री के हिसाब से खाद आवंटित किया जाएगा। समिति द्वारा की गई मांग के हिसाब से आपर्ति करने के पहले उसके द्वारा बीते एक सप्ताह में की गई बिक्री का हिसाब किताब देखा जाएगा। इसके साथ ही यह भी तय किया गया है कि समितियों को हर समय दो टन खाद का भंडारण रखना जरुरी रहेगा, जिससे कि किसानों को संकट का सामना न करना पड़े। खास बात यह है कि खाद की मांग और आपूर्ति संबंधी पूरी व्यवस्था ऑनलाइन रहेगी। इसकी वजह से राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) को स्टॉक की पूरी जानकारी हर समय अपडेट के साथ मिल सकेगी।

खाद की मांग भी बढ़ रही

प्रदेश में सिंचाई सुविधा में वृद्धि होने की वजह से लगातार खरीफ और रबी फसलों के

रकवे में भी वृद्धि हो रही है, जिसकी वजह से खाद की मांग भी बढ़ रही है। प्रदेश में अभी एक साल में 28 लाख टन यूरिया की जरुरत होती है। जरुरत के समय किसान को खाद की कमी न रहे और उसकी कालाबाजारी भी न हो पाए इसके लिए खाद भंडारण से लेकर उसके विक्रय तक की पूरी व्यवस्था ऑनलाइन की जा रही है।

कुछ समितियों को खाद की कमी

विभाग द्वारा सॉफ्टवेयर तैयार करा लिया गया है। इसके माध्यम से किसान और समितियों की जानकारी को एक-दूसरे से लिंक किया जा रहा है। इससे राज्य स्तर पर यह पता रह सकेगा कि किस समिति के पास किस कंपनी का कितना खाद है। समिति द्वारा की जा रही खाद की मांग सही है या नहीं। अभी कुछ समितियां आवश्यकता से अधिक खाद का भंडारण कर लेती है, जिसकी वजह से कुछ समितियों को खाद की कमी बनी रहती है।

निजी और सहकारी क्षेत्र को आधा-आधा खाद

इस बीच कृषि विभाग ने भी अब यूरिया वितरण व्यवस्था में बदलाव करने का निर्णय लिया है। इसके तहत अब निजी और सहकारी क्षेत्र को आधा-आधा खाद विक्रय के लिए दिया जाएगा। प्रदेश में बीते साल के नवंबर माह तक सहकारी क्षेत्र को 70 और निजी क्षेत्र को 30 फीसद यूरिया देने का निर्णय लिया गया था।

ऑनलाइन मांग स्वीकार

मांग और आपूर्ति के बीच इससे आने वाले अंतर की वजह से जब राज्य द्वारा केंद्र से खाद की मांग की जाती है, तो वह भंडार की स्थिति के चलते अतिरिक्त खाद देने से मना कर देता है। इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए ही यह नई व्यवस्था बनाई जा रही है। इससे खाद के विक्रय और भंडार की स्थिति के आधार पर ही ऑनलाइन मांग स्वीकार कर आपूर्ति की जाएगी।

मध्य प्रदेश में किसानों के हित में एक और नया कदम

अनाज खरीदी में बायोमैट्रिक्स सिस्टम रोकेगा धपला

प्रमुख संवाददाता, भोपाल

मध्य प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपज बेचने का फायदा सिर्फ वास्तविक किसानों को मिले, इसके लिए शिवराज सरकार नया कदम उठाने जा रही है। इसके तहत गेहूं, धान, चना, मसूर और सरसों बेचने के लिए उपार्जन केंद्रों पर आने वाले किसानों की पहचान बायोमैट्रिक्स सिस्टम से पुख्ता की जाएगी। इसमें आधार नंबर के माध्यम के किसान का सत्यापन होगा।

पाइंट ऑफ सेल्स मशीन (पीओएस) का उपयोग भी खरीद केंद्रों पर किया जाएगा। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ई-उपार्जन पोर्टल में दर्ज किसानों की जानकारी का मिलान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के किसानों से करवा रहा है। मध्य प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स डेवलपमेंट कार्पोरेशन को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है।

केंद्र पर पहचान पुख्ता होने के बाद खरीदेंगे उपज

सीएम शिवराज ने कराई थी जांच

मध्य प्रदेश में लगातार गेहूं, धान सहित अन्य फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद बढ़ती जा रही है। पिछले साल 129 लाख टन गेहूं खरीदकर प्रदेश ने पंजाब को पीछे छोड़ दिया था। धान की भी रिकॉर्ड खरीद हुई है। यही स्थिति अन्य अनाजों को लेकर भी है। लेकिन इस बीच बंपर खरीद को लेकर फर्जीवाड़े के आरोप भी लगते रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज ने स्वयं शिकायतें मिलने पर कलेक्टरों से जांच कराई थी।

किसानों के लाभ पर फोकस

दतिया, सागर सहित कुछ अन्य जिलों में अन्य राज्यों से उपज लाकर बेचने के मामले भी पकड़ाए थे। खाद्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि केंद्र सरकार भी चाहती है कि समर्थन मूल्य पर होने वाली खरीद का लाभ वास्तविक किसानों को ही मिले। इसके लिए व्यवस्थाओं को धीरे-धीरे ऑनलाइन किया जा रहा है। किसानों को उपज का भुगतान सीधे खातों में किया जा रहा है। वहीं, पंजीकृत किसानों से ही खरीद की व्यवस्था लागू की गई है।

इनका कहना है

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए भी किसानों की पूरी जानकारी जुटाई गई है। अब किसानों की जानकारियों का मिलान कराया जा रहा है। इसके आधार पर यह तय होगा कि वास्तव में कितने किसान समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेचते हैं। बायोमैट्रिक्स के आधार पर किसानों का सत्यापन कराने की पहल कर रहे हैं। राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम को इसके लिए तैयारी करने को कहा गया है।

■ **अभिजीत अग्रवाल,** प्रबंध संचालक, नागरिक आपूर्ति निगम

समर्थन पर गेहूं खरीदी की कमान संभालेंगी महिलाएं

इधर, प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए शिव सरकार द्वारा कई तरह की योजनाओं का संचालन पहले से ही किया जा रहा है। इनमें से कई तरह की योजनाओं का संचालन महिला स्व-सहायता समूहों के माध्यम से किया जा रहा है। सरकार ने अब इन्हें और अधिक सक्षम बनाने के लिए उन्हें समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का काम भी देने का फैसला कर लिया है। फिलहाल प्रयोग के तौर पर अभी इस सीजन में कुल खरीदे जाने वाले गेहूं (रबी उपार्जन) में से 10 फीसदी खरीदी स्व-सहायता समूहों की महिलाएं से कराने का तय किया है। गौरतलब है कि इस रबी सीजन में 40 लाख क्विंटल गेहूं की खरीदी महिला स्व-सहायता समूहों से कराने का लक्ष्य तय किया गया है। मप्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने कृषि एवं खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति विभाग के साथ मिलकर महिला समूहों से गेहूं खरीदी कराने का तीन जिलों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। इसके अच्छे परिणाम सामने आने के बाद ही इस तरह का निर्णय लिया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के चलते ही जबलपुर में एक-एक समूह को इससे कमीशन के रूप

- **पायलट प्रोजेक्ट के तहत जबलपुर से होगी शुरुआत**
- **एक-एक समूह को कमीशन के रूप में 18 लाख मिले**

में 18 लाख रुपए तक कमीशन मिल चुका है। यह पहला अवसर है जब उपार्जन का कार्य महिलाओं के स्व-सहायता समूहों से इतने बड़े स्तर पर कराया जा रहा है। फिलहाल कितने जिलों में कितने सेंटर महिला समूहों को दिए जाएंगे अभी इसकी तैयारी की जा रही है।

की जा चुकी है धान की खरीदी: इसके पहले आजीवका मिशन के समूहों द्वारा बड़े पैमाने पर धान खरीदी का काम किया जा चुका है। यह धान 10 जिलों के 32 सेंटरों पर महिलाओं द्वारा खरीदा गया है। इन सेंटरों पर 7 लाख क्विंटल धान की खरीदी की गई है। गेहूं के उपार्जन के लिए गोदाम स्तर पर खरीदी केन्द्रों के निर्धारण को प्राथमिकता दी जा रही है। इन्हीं केन्द्रों को ज्यादा से ज्यादा महिला स्व-सहायता समूहों को दिए जाने की संभावना है।

प्रदेश में बढ़ाना पड़ रहा खरीदी का दायरा

■ **उपार्जन केन्द्रों में मनरेगा के तहत कैंप किए जा रहे तैयार**

मध्य प्रदेश में इस बार गेहूं उपार्जन का नया रिकॉर्ड बनना तय माना जा रहा है। इसकी वजह से एक बार फिर मप्र द्वारा गेहूं के उपार्जन में पिछले साल की ही तरह पंजाब को पीछे छोड़ना तय माना जा रहा है। फिलहाल अनुमान है कि इस बार प्रदेश में गेहूं का उपार्जन डेढ़ करोड़ मीट्रिक टन तक पहुंचने की संभावना है। यही वजह है कि इस बार सरकार को न केवल खरीदी का दायरा बढ़ाना पड़ रहा है, बल्कि अभी से भंडारण की व्यवस्था भी बड़े पैमाने पर करनी पड़ रही है। गत वर्ष प्रदेश में एक करोड़ 29 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की गई थी। इसी वजह से इस मामले में पंजाब को पहली बार दूसरे स्थान पर रहने को मजबूर होना पड़ा था।

प्रदेश में अभी तक यह काम मप्र राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा किया जाता है। सरकार की यही एजेंसी सहित रबी सीजन में मसूर, चना और सरसों की खरीदी का काम भी करती है। अब इस बार प्रदेश में करीब डेढ़ करोड़ मीट्रिक टन की गेहूं खरीदी संभावित है, जिसकी वजह से राज्य सरकार द्वारा खरीदी का दायरा भी बढ़ाने का फैसला कर लिया गया है।

उपार्जन की प्रक्रिया शुरू

प्रदेश में रबी उपार्जन का काम 15 मार्च से शुरू हो गया है। इसके तहत सबसे पहले चना और सरसों के उपार्जन का काम किया जाएगा। इसकी खरीदी 15 मई तक चलेगी। गेहूं की खरीदी का काम 22 मार्च से शुरू होकर 15 मई तक जारी रहेगा। हालांकि उसके बाद भी खरीदी के समय में वृद्धि की जा सकती है।

मनरेगा के तहत तैयार होंगे कैंप

प्रदेश में इस बार बंपर गेहूं की आवक की संभावना को देखते हुए उपार्जित अनाज को बारिश से बचाने तथा अधिक उपार्जन वाले केन्द्रों में मनरेगा योजना के तहत कैंप तैयार करने का काम किए जाने का फैसला किया गया है। कैप में गेहूं को तब तक सुरक्षित रखा जाएगा, जब तक कि उसे सुरक्षित गोदामों में रखने की व्यवस्था नहीं कर ली जाती है।

वानिकी विकास योजनाओं से संवर रहा है मध्यप्रदेश का ग्रामीण परिवेश

ऋषभ जैन
जनसंपर्क अधिकारी

मध्यप्रदेश में वनों के संरक्षण और संवर्धन के लिए की जा रही प्रभावी पहल के चलते वनों के साथ-साथ उन पर आश्रित आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को वानिकी विकास के जरिए समृद्ध किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में पिछले एक साल में वनों की सुरक्षा और विकास के साथ-साथ वनों पर आश्रित वनवासियों के कल्याण की नई इबारत लिखी गई है।

मध्यप्रदेश में वनों के संरक्षण और संवर्धन के लिए की जा रही प्रभावी पहल के चलते वनों के साथ-साथ उन पर आश्रित आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को वानिकी विकास के जरिए समृद्ध किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में पिछले एक साल में वनों की सुरक्षा और विकास के साथ-साथ वनों पर आश्रित वनवासियों के कल्याण की नई इबारत लिखी गई है। प्रदेश में वन-जन को समन्वित कर वानिकी में भागीदारी का अंश बढ़ाने के साथ ही जन की सक्रियता बढ़ाने के उद्देश्य से संयुक्त वन प्रबंधन की विचारधारा को सशक्त रूप से अपनाया गया है। संयुक्त वन प्रबंधन के लिए 9784 ग्राम वन, 4773 वन सुरक्षा और 1051 ईको विकास समितियां गठित हैं। इनके माध्यम से करीब 47 हजार वर्ग किलो मीटर वन क्षेत्रों का प्रबंधन किया जा रहा है।

वन समितियों में 33 फीसदी महिलाओं की सदस्यता आरक्षित की गई है। साथ ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद में से एक पर महिला की नियुक्ति अनिवार्य की जाकर महिला सशक्तिकरण को प्रभावी बनाया गया है।

वन खंड की सीमा से 5 किमी दूरी तक स्थित ग्रामों में गठित वन सुरक्षा समिति सघन वन क्षेत्रों में अवैध कटाई, चराई और अग्नि से क्षेत्र की सुरक्षा का काम करती हैं। इसके ऐवज में उन्हें आवंटित क्षेत्र से समस्त लघु वनोपज, रॉयल्टी मुक्त निस्तार एवं काष्ठ विदोहन का 20 प्रतिशत लाभांश दिया जाता है। जैव विविधता के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य के बफर क्षेत्र की सीमा से 5 किमी की परिधि में स्थित ग्रामों में ईको विकास समिति गठित है। यह समितियां सामाजिक-आर्थिक उत्थान के कार्य में संलग्न हैं।

जिलास्तर पर काष्ठ विदोहन से हुए शुद्ध लाभ 20 फीसदी वन प्रबंधन समितियों को 22 करोड़ 56 लाख रुपए की राशि दी गई। बांस कटाई में संलग्न श्रमिकों को बांस विदोहन से प्राप्त शुद्ध लाभ की राशि शत-प्रतिशत दी जाती है। इसमें 11 करोड़ 39 लाख का लाभांश दिया जा चुका है। इस तरह कुल 33 करोड़ 95 लाख का लाभांश वितरित किया जा चुका है। प्रदेश के किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कृषि फसलों के साथ बांस रोपण एक बेहतर विकल्प के रूप में लोकप्रिय हुआ है। इस वित्त वर्ष में 3597 किसानों ने 3228 हेक्टेयर क्षेत्र में बांस रोपण किया। जिस पर उन्हें पौने 7 करोड़ से ज्यादा का अनुदान दिया गया। स्व-सहायता समूहों को आत्म-निर्भर बनाने के लिए मनरेगा में 83 स्व-सहायता समूह के माध्यम से 1020 हेक्टेयर क्षेत्र में बांस रोपण किया गया। अन्य योजनाओं में भी 1248 हेक्टेयर क्षेत्र में बांस रोपण किया गया। निजी क्षेत्र में मंजूर की गई 13 बांस प्र-संस्करण इकाइयों में से 9 इकाई प्रारंभ हो चुकी है। इन इकाइयों को 1 करोड़ 68 लाख का अनुदान वितरित किया गया। इस वित्त वर्ष में शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए अब तक करीब एक हजार छात्र-छात्राओं को 9 करोड़ 88 लाख से ज्यादा की सहायता दी गई। लघु वनोपज संघ द्वारा एकलव्य शिक्षा विकास योजना के जरिए तेन्दूपत्ता संग्राहकों, फड़-मुंशी और प्रबंधकों के बच्चों की शैक्षणिक गतिविधियों में सहायता प्रदान कर उनका भविष्य संवारा जा रहा है। प्रदेश में तेन्दूपत्ता संग्रहण में 33 लाख संग्राहक जुड़े हैं। इनमें 44 फीसदी महिलाएं हैं। अधिकत्तर संग्राहक अनुसूचित जाति/जनजाति और पिछड़ा वर्ग के हैं। इन्हें लगभग एक माह का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। इन संग्राहकों को आर्थिक संबल देने के लिए तेन्दूपत्ता संग्रहण का पारिश्रमिक तथा प्रोत्साहन पारिश्रमिक बोनस के रूप में दिया जाता है। पिछले वर्ष 15 लाख 88 हजार मानक बोरा तेन्दूपत्ता संग्रहीत कर संग्राहकों को 397 करोड़ का पारिश्रकि दिया गया। वर्ष 2018 में संग्रहीत और तेन्दूपत्ते के व्यापार से हुए शुद्ध लाभ में से 183 करोड़ 31 लाख की राशि प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में दी गई। मुख्यमंत्री तेन्दूपत्ता संग्राहक सहायता योजना में इस वित्त वर्ष में अब तक 2 करोड़ 26 लाख 20 हजार की सहायता राशि वितरित की जा चुकी है। लघु वनोपज के संग्राहकों द्वारा संग्रहीत वनोपज का प्राथमिक उपचार कर सही मूल्य प्राप्त हो सके, इसके लिए वन-धन विकास योजना के तहत ट्राइफेड द्वारा पहले चरण में 13 जिलों में 86 वन-धन विकास केन्द्र स्थापित किए गए हैं। इनमें 10 स्व-सहायता समूह क्लस्टर का एक केन्द्र है। इसमें प्रत्येक स्व-सहायता समूह के 30 सदस्य रखे गए हैं। इससे 50 करोड़ का व्यापार संभावित है। प्रदेश में 32 लघु वनोपजों का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। खास बात यह है कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर के समकक्ष और कुछ वनोपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार की दरों से भी ज्यादा है। लघु वनोपज संग्राहकों द्वारा संग्रहीत वनोपज का प्राथमिक प्र-संस्करण एवं मूल्य संवर्धन द्वारा उचित मूल्य दिलाने के लिए यह अभिनव योजना शुरू की गई है। एक वन-धन केन्द्र में 300 संग्राहक हैं। राज्य लघु वनोपज संघ, क्रियान्वयन ऐजेन्सी है। प्रदेश में वानिकी वृत्तों की 170 रोपणियां हैं। इन रोपणियों से 3 करोड़ 42 लाख पौधों की बिक्री और 50 लाख सागौन रूट-शूट की नीलामी से 4 करोड़ 99 लाख रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। इस वर्ष रोपण के लिए पौधा तैयारी का कार्य भी प्रगति पर है। रोपणियों के पौधों को ऑन-लाईन संधारण के लिए नर्सरी मैनेजमेन्ट विकसित किया गया है। कुछ रोपणियों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाकर उनकी सुरक्षा और निगरानी की जा रही है। वनोपज की मांग और आपूर्ति के बढ़ते अन्तर को कम करने और किसानों की आर्थिक समृद्धि के लिए निजी भूमि पर वनीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्ष 2020 में गैर वन क्षेत्रों में विभिन्न प्रजाति के करीब सवा 6 लाख पौधों का रोपण कराया गया। आम लोगों को एमपी ऑन-लाईन के माध्यम से भी पौधे उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की गई है। वनों की संवहनीयता बनाए रखने के लिए बिगड़े वनों का सुधार, पौधरोपण आदि कार्य किए जाते हैं।

कृषि कानून विरोधी आंदोलन के बहाने किसान नेताओं ने पकड़ी पगडंडी

भूपेंद्र सिंह

किसान नेता अपने आंदोलन को राजनीतिक शक्ल देकर इस या उस दल के साथ खड़े हो जाएं, लेकिन उन्हें आम जनता को परेशान करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। सड़कों को घेरने की हरकतें कानून एवं व्यवस्था का उपहास ही उड़ा रही हैं।

चंद किसान संगठनों की ओर से जारी कृषि कानून विरोधी आंदोलन जिस तरह खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, वह केवल किसान नेताओं की जिद को ही जाहिर नहीं करता, बल्कि यह भी बताता है कि वे किस तरह किसानों के साथ छल करने में लगे हुए हैं। जो किसान नेता यह बहाना बनाने में लगे हुए थे कि उनका राजनीतिक दलों से कोई लेना-देना नहीं, वे इन दिनों बंगाल के दौरे पर हैं और ममता बनर्जी को जिताने की अपील करने में लगे हुए हैं। उनकी इस पैंतरेबाजी से उन्हें खुलकर समर्थन देने वाले वाम दल भी असहज हैं। यह तो समझ आता है कि किसान नेता चुनाव वाले राज्यों में पहुंचकर भाजपा को हराने की अपील करें, लेकिन किसी के लिए भी यह समझना कठिन है कि आखिर वे बंगाल पहुंचकर उस ममता सरकार की पैरवी कैसे कर सकते हैं, जिसने संकीर्ण राजनीतिक कारणों से अपने राज्य के किसानों को किसान सम्मान निधि से वंचित कर रखा है? साफ है कि इन किसान नेताओं को आम किसानों के हितों की कहीं कोई परवाह नहीं। यह इससे भी स्पष्ट होता है कि वे उस नियम का विरोध करने के लिए आगे आ गए हैं, जिसके तहत केंद्र सरकार ने यह तय किया है कि सरकारी खरीद वाले अनाज का पैसा सीधे किसानों के खाते में जाएगा। यह व्यवस्था किसानों को बिचौलियों और विशेष रूप से आढ़तियों की मनमानी से बचाने के लिए की गई है, लेकिन हैरानी की बात है कि किसान नेताओं को यह रास नहीं आ रहा है। आश्चर्यजनक रूप से पंजाब सरकार भी इस व्यवस्था से कुपित है।

किसान नेता किस तरह अपने आंदोलन के नाम पर किसानों को गुमराह कर उन्हें बदनाम करने का काम कर रहे हैं, इसका पता उनकी ओर से दिल्ली सीमा पर सड़कों पर पक्के मकान बनाने से चलता है। यह अंधेरगर्दी और अराजकता के अलावा और कुछ नहीं। इस अराजकता पर इसलिए अंकुश लगाया जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली-एनसीआर के लाखों लोगों को प्रतिदिन घोर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब जब यह स्पष्ट है कि किसान नेता मनमानी पर आमादा हैं, तब फिर इसका कोई औचित्य नहीं कि आम लोगों को जानबूझकर तंग करने वाली उनकी हरकतों की अनदेखी की जाए। इसमें कोई हर्ज नहीं कि किसान नेता अपने आंदोलन को राजनीतिक शक्ल देकर इस या उस दल के साथ खड़े हो जाएं, लेकिन उन्हें आम जनता को परेशान करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। सड़कों को घेरने और टोल नाकों पर कब्जा करने की हरकतें कानून एवं व्यवस्था का उपहास ही उड़ा रही हैं। कोई भी आंदोलन हो, उसकी आड़ में अराजकता स्वीकार्य नहीं।

ऑनलाइन शिक्षा को अपनाना आवश्यक: प्रो. नागेश्वर राव

कोरोना महामारी के कारण प्रत्येक क्षेत्र को कुछ न कुछ समयानुकूल समाधान निकालने पड़े हैं। इसी कड़ी में शिक्षा क्षेत्र को ऑनलाइन शिक्षा जैसा माध्यम अपनाना पड़ा। चूंकि आत्मनिर्भर भारत की बड़ी योजना का अहम पक्ष शिक्षा से जुड़ा हुआ है और यहां एक बड़ी युवा आबादी भी है तो ऐसा कोई समाधान तलाशना आवश्यक ही नहीं, अपितु अनिवार्य था। ऑनलाइन शिक्षा संसाधन और इच्छाशक्ति, दोनों की मांग करती है और भारत ने इन दोनों ही मोर्चों पर अच्छा प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री ई-योजना के तहत 50 लाख विद्यालय और 50 हजार से अधिक उच्च शिक्षण संस्थाओं को डिजिटल बनाने की योजना बन चुकी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने भी कहा है कि दुनिया के सामने भारत एक मानक बन सकता है। यह अच्छा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को भी ऑनलाइन शिक्षा के साथ सुसंगत किया गया है। यह स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं कि परंपरागत शिक्षा व्यवस्था में कुछ मूलभूत अड़चनें भी हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद उच्च शिक्षण संस्थानों में नामांकन एलिमिनेशन अर्थात विलोपन के आधार पर होता है। जैसे कि दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों में नामांकन पैमाना 99 प्रतिशत और यहां तक शत प्रतिशत अंकों तक जाता है। देश के अन्य प्रतिष्ठित महाविद्यालयों की भी कमोबेश यही स्थिति है। आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े समाज के बच्चों के लिए 90 प्रतिशत का स्तर पाना ही मुश्किल है। इसके उलट यदि ऑनलाइन शिक्षा की बात करें तो यहां एलिमिनेशन के आधार पर नामांकन नहीं, बल्कि विद्यार्थियों की इच्छाशक्ति के आधार पर होता है। भारत में उच्च शिक्षण संस्थाओं में नामांकित विद्यार्थियों की तादाद कई यूरोपीय देशों की जनसंख्या से भी अधिक है। अगर क्लास रूम और ब्लैक बोर्ड तक शिक्षा सिमटी रहती है तो करोड़ों बच्चे उच्च शिक्षा से वंचित रह सकते हैं। सभी विद्यार्थियों के लिए संस्थान बनाने का रोडमैप भी अत्यंत कठिन है। यह विशालकाय हाथी की तरह है, जिसका पालन-पोषण अत्यंत खर्चीला और चुनौतीपूर्ण है। वहीं ऑनलाइन शिक्षा में यह स्थिति बदल जाती है। अगर ऑनलाइन के आधार पर शिक्षा की बात की जाए तो उसमें न ही जमीन की जरूरत है और न ही भारी भरकम संसाधन की। ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था पर अमेरिकी शोध संस्थाओं की रिपोर्ट भी इसकी पुष्टि करती है। समकालीन विश्व व्यवस्था में ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से भारत की धाक जम सकती है। कई आंकड़े भारत के पक्ष में है। वर्ष 2030 तक दुनिया में कामगार लोगों की सबसे बड़ी जमात भारत में होगी। भारत सरकार की योजना और सोच भी है कि 2035 तक उच्च शिक्षण संस्थाओं में सकल नामांकन अनुपात यानी जीईआर के आंकड़े को 50 प्रतिशत तक पहुंचाना है, जो अभी 25 फीसद पर अटका हुआ है। विकसित देशों में यह आंकड़ा 80 से 90 प्रतिशत के बीच है। इस बीच अहम सवाल यही है कि क्या पारंपरिक शिक्षा के माध्यम से यह लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। संसाधनों की दृष्टि से तो यह संभव नहीं लगता। इसका दूसरा पक्ष गुणवत्ता से जुड़ा है। हजारों संस्थान बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने में असफल भी रहते हैं। स्पष्ट है कि जीईआर को 50 प्रतिशत तक लाना दुष्कर है। इसके लिए भारत को ऑनलाइन मोड में जाना ही पड़ेगा। यह एक सार्थक और बेहतर विकल्प है। इसमें वैश्विक समावेश की भी गुंजाइश भी है। बस आवश्यक है विश्व के बेहतरीन विश्वविद्यालयों के साथ भारतीय सोच को विकसित करने की। इससे भारत की वैश्विक तस्वीर भी बदलेगी। विशेषकर दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया और अफ्रीकी देशों के करोड़ों विद्यार्थी भारतीय शिक्षा व्यवस्था से जुड़ जाएंगे। मल्टी मीडिया के जरिये ऑनलाइन शिक्षा को रुचिकर और ज्ञानवर्धक बनाने में मदद मिलेगी। अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय की 2019 में आई रिपोर्ट में इस बात की व्याख्या है कि ऑनलाइन माध्यम में बच्चों की शिक्षा और मूल्यांकन ज्यादा गुणवत्तापूर्ण रहा है। शिक्षक का भी विद्यार्थियों के साथ अकादमिक संपर्क अधिक सशक्त होता है। पिछले कुछ वर्षों में इंटरनेट की पहुंच भारत के गांव-गांव तक हो गई है। भारत ब्रॉडबैंड मिशन के तहत वर्ष 2022 तक देश के सभी गांवों और शहरों को इंटरनेट से जोड़ दिया जाएगा। इसलिए ऑनलाइन शिक्षण संस्थान ही देश को बदलने में कारगर हो सकते हैं। डिजिटल भारत ही दुनिया के सामने एक मानक बन सकता है। देश के पास ऑनलाइन के सारे साधन मौजूद हैं, बस हमें पारंपरिक सोच के बजाय आधुनिक दृष्टिकोण के साथ सटीक रणनीति बनानी होगी। ऑनलाइन शिक्षा की राह में चुनौतियां भी कम नहीं हैं।

वदौआ पंचायत को आत्मनिर्भर बनाना ही अब मेरा लक्ष्य

संवाददाता, भोपाल/रीवा

मध्यप्रदेश के रीवा जिले की मनगवां विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत वदौआ के सरपंच प्रमोद कुमार द्विवेदी का लक्ष्य है कि उनकी ग्राम पंचायत वदौआ आत्मनिर्भर बने। गांव के लोगों को गांव में ही रोजगार के भरपूर अवसर मिलें। साथ ही गौ सरक्षण को बढ़ा दिया जाए। वो चाहते हैं कि अगर राज्य सरकार से मंजूरी मिल तो अपनी पंचायत में एक बड़ी गौशाला का निर्माण भी कराऊंगा। हमारे पंचायत के किसान आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। किसान पुत्र हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जितनी भी योजनाएं हैं, उनमें सबसे ऊपर पंचायत और किसान ही हैं। सीएम की दूरदर्शीता का ही नतीजा है कि मप्र को सात बार कृषि कर्मण अवार्ड से नवाजा जा चुका है और सब ठीक-ठाक रहा तो इस साल भी यह सम्मान मप्र के ही खाते में आएगा। **जागत गांव हमार** के सावलों का सरपंच ने बेबाकी से दिया जवाब। बातचीत के मुख्य अंश

सरपंच प्रमोद कुमार द्विवेदी ने बिछा दिया सड़कों का जाल

सवाल: आपके कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है?

जवाब: मेरी ग्राम पंचायत वदौआ में एक भी सड़क नहीं थी। बारिश के दिनों में लोग अपने ही घरों में कैद हो जाते थे। किसी को अस्पताल ले जाना होता था तो वाहन नहीं आ पाते थे। लेकिन आज मेरी पंचायत की स्थिति बदल चुकी है। मैंने अपने कार्यकाल में सड़कों का जाल बिछा दिया है। अब घर-घर गाड़ियां आती हैं। स्थानीय लोग भी ये स्वीकारते हैं कि विकास कार्यों से पंचायत की सूरत बदल गई है। पूरे पंचायत में दो दर्जन के करीब पीसीसी रोड बनवाई गई हैं।

सवाल: राजनीति में सरपंच पद का चुनाव ही क्यों चुना?

जवाब: असली भारत गांव में ही बसता है। गांव के विकास से ही प्रदेश और देश आगे बढ़ता है। बचपन से ही अपने गांव की दुर्दशा देखकर मैं कुछ अलग करना चाहता था। इसलिए सरपंच का चुनाव लड़ा और जनता ने मुझ पर भरोसा किया। भारी मतों से विजयी बनाया। राजनीति मैं पैसा और नाम कमाने के लिए नहीं, बल्कि अपने गांव वासियों की सेवा के लिए कर रहा हूं।

सवाल: अब तक कितने हितग्राहियों को पीएम आवास मिले?

जवाब: मेरे कार्यकाल में पचायत में 350 पीएम आवास स्वीकृत हुए हैं। इसमें 16 हितग्राहियों को मिल भी चुके हैं। जो शेष हैं, उन्हें भी पीएम आवास मिल जाएगा। मेरा लक्ष्य है कि वदौआ पंचायत में गरीब के पास पक्का मकान हो। यहां सबसे अधिक 500 हरिजन बस्ती, 300 पिछड़ा वर्ग और 500 सामान्य बस्ती हैं। मैं चाहता हूं कि मेरी पंचायत मप्र के लिए रोल मॉडल बने।

सवाल: कुछ लोग कहते हैं कि पंचायत में भ्रष्टाचार भी खूब हुआ है?

जवाब: मैं किसी के कहने पर नहीं, विकास पर यकीन करता हूं। मैंने जो काम किया है वो जनता के सामने है। रही बात भ्रष्टाचार की तो कहने वाले कुछ भी कहते रहते हैं। अगर मैं भ्रष्टाचार करता तो मेरे द्वारा कराए गए विकास कार्यों की जिले भर में सराहना नहीं होती। तब मुझे मुख्यमंत्री सम्मान नहीं मिलता।

सवाल: वदौआ ग्राम पंचायत में शौचालय की क्या स्थिति है?

जवाब: वदौआ ग्राम पंचायत खुले में शौच मुक्त घोषित हो चुकी है। रीवा जिले की दूसरी पंचायत है मेरी, जिसे तत्कालीन

कलेक्टर राहुल जैन ने खुले में शौच मुक्त घोषित किए थे। आज हर घर पक्के शौचालय बने हैं। लोग अब बाहर नहीं जाते। पहले लोगों को जागरुक करने के लिए मैंने अपनी पंचायत में तीन-चार कैमरा मैन तैनात किए थे। बाहर गंदगी फैलाने पर फोटो खिंचवा लेता था। धीरे-धीरे लोग भी समझ गए और शौच के लिए बाहर जाना बंद कर दिया।

सवाल: घर-घर पीने का पानी पहुंचाने की ग्राम में क्या स्थिति है?

जवाब: मध्यप्रदेश सरकार ने घर-घर पीने का पानी पहुंचाने का जो लक्ष्य तय किया है, उसके तहत मेरी पंचायत में चार पानी की टंकियां स्वीकृत हो चुकी हैं। जिसमें दो बड़ी टंकियां होंगी और दो छोटी। अप्रैल से सभी टंकियों का निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। इससे सबसे अधिक हरिजन और पिछड़ा वर्ग की बस्तियां लाभान्वित होंगी। वदौआ ग्राम पंचायत में आज कम से कम 50 हैंडपंप हैं। अधिकांश चालू हालत में हैं। हमारे गांव का जल स्तर काफी अच्छा है। कुल मिलाकर गेहूं-धान प्रधान मेरी पंचायत है।

कोरोना काल के लॉकडाउन में श्रमिकों को मिला काम

सवाल: पंचायत में विकास के प्रति प्रशासनिक रवैया कैसा है?

जवाब: पंचायत में प्रशासनिक सहयोग से ही तो विकास होता है। जिला और जनपद पंचायत सीईओ, इंजीनियर, सचिव और जीआरएस का विकास के प्रति काफी अच्छा सहयोग रहता है। जिस तरह से गांव विकास के लिए मैं तत्पर रहता हूं, उसी तरह प्रशासनिक अधिकारी भी विकास कार्यों को लेकर जूझते नजर आते हैं। बीच-बीच में मेरा मार्गदर्शन भी करते हैं।

सवाल: आपकी पंचायत में तालाब और मेड़ बंधान की क्या स्थिति है?

जवाब: हमारी पंचायत में पानी की काई कमी नहीं है। सबसे पहले मैंने बड़े तालब का जीर्णोद्धार कराया था। जो आज भी लबालब भरा हुआ है। इसी तरह शासन की योजना के तहत छह खेत तालब का निर्माण कराया। उनमें भी भरपूर पानी है। मैंने चार दर्जन के करीब किसानों के खेतों में मेड़ बंधान कराए।

किस्सा-ए-आलू: बिचौलिये मालामाल, किसान बदहाल

» मंडियों में थोक दाम गिरकर पांच प्रति किलो तक पहुंच गए

» भाव नहीं मिलने से मालवांचल में बिचौलिए उठा रहे फायदा

» परेशान किसान बोले- परिवहन का खर्च भी नहीं निकल रहा

संवाददाता, मालवा-निमाड़। अंचल में इस बार आलू का उत्पादन बंपर हुआ है और बेहतर भी, लेकिन यह पैदावार अन्नदाता किसान के लिए राहत लेकर नहीं आई है। मंडियों में आवक बढ़ते ही थोक दाम गिरकर पांच रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए। जो आलू बीते वर्षों में किसानों के लिए फायदे का सौदा रहा, वह अब रुला रहा है। आवक का आलम यह है कि कोल्ड स्टोरेज में रखने को जगह तक नहीं बची। फिर भी आम उपभोक्ता की जेब का भार कम नहीं हो रहा। फुटकर में आलू 15-20 रुपए किलो ही है। जाहिर है, फायदा बिचौलिए उठा रहे हैं।

उज्जैन: 3.22 लाख टन उत्पादन

उज्जैन जिले में अधिकांश क्षेत्रों में किसान आलू की पैदावार में लगे हैं। हर वर्ष इसकी खेती फायदे का सौदा बन रही थी, लेकिन इस बार बंपर उत्पादन के बाद भी अच्छे भाव नहीं मिल रहे, जबकि मौसम की अनुकूलता के चलते क्वालिटी भी उम्दा है। जिले में इस बार 13,300 हेक्टेयर में आलू की बोवनी की गई थी। 3.22 लाख हजार टन उत्पादन हुआ। बंपर उत्पादन के चलते किसान आलू बेचने मंडी पहुंच रहे हैं। यहां उन्हें उचित दाम नहीं मिल रहे हैं। थोक में पांच रुपए किलो में बिक रहा है। आधे से ज्यादा कोल्ड स्टोरेज फुल हो चुके हैं।

शाजापुर :16 कोल्ड स्टोरेज फुल

शाजापुर जिले में आलू की 5,325 हेक्टेयर में फसल बोई गई है। वर्तमान में थोक में आलू तीन से 10 रुपए किलो बिक रहा है। खेरची भाव 10 से 15 रुपए किलो है। दो माह में दाम 10 रुपए किलो तक टूटे हैं। आवक भी लुढ़की है। मंडी में 500 कट्टे के आसपास आवक है। किसान कोल्ड स्टोरेज में आलू रखना चाह रहे हैं। जिले के 16 कोल्ड स्टोरेज फुल हैं, जिनकी क्षमता 8 लाख क्विंटल है।

रतलाम :6,600 मीट्रिक टन उत्पादन

जिले में 330 हेक्येयर में आलू की खेती हो रही है। प्रति हेक्टेयर 20 मीट्रिक टन उत्पादन होता है। करीब 6,600 मीट्रिक टन उत्पादन होता है। आलू थोक में आठ से बारह रुपए प्रति किलो बिक रहा है। वहीं खुदरा बाजार में 15 से 25 रुपए किलो दाम है। यहां के आलू से चिप्स बनाई जाती है। मंडी में जिले के अलावा आगरा आदि स्थानों का आलू भी बिकने आता है। जिले के दोनों कोल्ड स्टोरेज भरने के करीब हैं।

देवास: किसानों को हो रहा नुकसान

देवास जिले में आलू का रकबा लगभग दस हजार हेक्टेयर है। कुल उत्पादन करीब दो लाख मीट्रिक टन हुआ है। जिले में 14 कोल्ड स्टोर है, जिनकी क्षमता 5 हजार मीट्रिक टन है। सभी कोल्ड स्टोरेज भरने के करीब हैं। जिले में डेढ़ लाख टन क्षमता के 35 कोल्ड स्टोरेज हैं। उत्पादन के मान से यह क्षमता आधी से भी कम है। सभी फुल हो गए हैं। नतीजतन किसानों को आलू औने-पौने भाव में बेचकर नुकसान उठाना पढ़ रहा है।

फुटकर 15 रुपए किलो

किसानों को मंडी में दाम भले ही कम मिलें, आम नागरिकों को यह अधिक भाव में ही मिल रहा है। फुटकर सब्जी मार्केट में आलू 15 रुपए किलो तक बिक रहा है।

प्याऊ से बुझाएंगे गौमाता की प्यास

» इंदौर के लिए गौभक्तों ने जुटाई पानी की 30 टंकियां

» टंकियों की मदद से 24 घंटे मिलेगा पीने का पानी

संवाददाता, इंदौर

गौभक्त गर्मी में गौमाता की प्यास बुझाएंगे। इसके लिए भक्तों ने एक-दूसरे को संदेश भेजकर अब तक 30 टंकियां एकत्र कर ली हैं। इन टंकियों को उपयोग जिले की उन जरूरतमंद गौशालाओं में किया जाएगा, जहां गर्मी के दिनों में गायों को पानी की बूंद-बूंद के लिए संघर्ष करना पड़ता है। एक हजार लीटर पानी की क्षमता वाली इन टंकियों का नि:शुल्क वितरण इसी माह किया जाएगा। इस ग्रीष्मकाल में लक्ष्य 50 टंकियों के वितरण का है।

मां पराम्बा गौभक्त मंडल के तत्वावधान में शहर के कुछ गौभक्तों ने अपने स्तर पर यह अनूठी पहल शुरू की है। गौरतलब है कि अधिकांश गौशालाओं में पानी की ठेल पर गायें या तो आपस में पहले पानी पीने के लिए लड़ती हैं या ठेल का पानी खत्म होने पर प्यासी ही रह जाती हैं। इन टंकियों को गौशाला के विद्युत पंप से जोड़कर ठेल तक पाईप लाईन की मदद से जैसे ही पानी खाली होगा, फिर से भर दिया जाएगा। इस तरह अब गायों को पूरे वर्ष 24 घंटे पर्याप्त पानी मिल सकेगा। इससे पानी का अपव्यय भी बच जाएगा। इस पूरी योजना को उन्होंने 'गौ प्याऊ' नाम दिया है।

हर टंकी में एक हजार की छूट

फिलहाल शहर के गौभक्तों की ओर से 30 टंकियां प्राप्त हो चुकी हैं जो गौकुलम गौशाला रेशम केंद्र पर रखी गई हैं। इन टंकियों के लिए दानदाताओं ने भुगतान सीधे टंकी विक्रेता पूरणमल मुरारीलाल पालड़ीवाल के खाते में आरटीजीएस किया है। भक्त मंडल ने किसी भी तरह की नगद राशि हाथ में नहीं ली है। टंकी विक्रेता ने भी इस संकल्प के लिए प्रत्येक टंकी पर एक हजार रुपए की रियायत दी है।

अभी इन्होंने दी सहमति

अब तक इन टंकियों के लिए लक्ष्मीबाई जगदीशचंद्र होलानी, मोहनी देवी मदनलाल समदानी चेरिटेबल ट्रस्ट मुंबई, दिलीप जैन सेक्रेटरी परिवार कुक्षी, द्वारकेश दुबे मित्र मंडल, अरिहंत रानी नाहर, विशाल नाहर मुंबई, मुदित मकवाना, पुनीत खंडेलवाल, मनीष धारीवाल, राजेश अग्रवाल, कपिल महाराज, विवेक पाठक, चंद्रभूषण आदि ने लाभार्थी बनने पर सहमति प्रदान की है।

साढ़े तीन हजार गायों को मिलेगा पीने का पानी

जो टंकियां गुप्त दान के रूप में प्राप्त हुई हैं, उन पर गौरक्षक संत एवं देश के शहीदों के नाम अंकित किए जाएंगे। जिन गौशाला में इन टंकियों के माध्यम से गायों को जल वितरण की व्यवस्था लागू की जाएगी, उनमें आदिनाथ जैन गौशाला गांधी नगर में 100, श्री ओमानंद गौशाला देवधरम में 80, रामकृष्ण रामस्नेही गौशाला हातोद में 150, गोकुलम गौशाला रेशम केंद्र पर 40, श्रीकृष्ण बलदाऊ गौधाम सिकंदरी में 250, गंगा गौशाला गंगाजलखेड़ी में 175, अटल हनुमान गौधाम गौशाला देवड़ाखेड़ी में 250, धरावराधाम गौशाला में 400, श्रीराम-जानकी गौसेवा समिति बेटमा में 475, श्रीमद ओम गायत्री गौशाला कजलीगढ़ में 250, ओखलेश्वर गौशाला में 45, देपालपुर स्थित चौवीस अवतार मंदिर पर 100, मुरारीलाल तिवारी गौशाला उज्जैन रोड 327, संत ज्ञानीजी की गौशाला कनवासा में 80, गौतमपुरा गौशाला पर 100, गोमती परमधाम गौशाला खातेगांव पर 200 एवं मधुसूदन गौशाला धामनदा पर 400, श्रीमद भागवत सेवा गौशाला कैलोद करताल पर 40 गौवंश के लिए इन टंकियों की मदद से गौवंश को पूरे वर्ष भर 24 घंटे पानी मिल सकेगा, जिससे मोटे तौर पर साढे तीन हजार से अधिक गायों की प्यास बूझ सकेगी।

'गौ प्याऊ' योजना तहत देपालपुर तहसील की आठ, सांवेर की 5, इंदौर की 14, देवास की एक, राजगढ़ जिले की एक, ओंकारेलश्वर की एक, इस तरह 30 गौशालाओं को पहले चरण में ये टंकियां भेंट की जा रही हैं। ताकि इनकी मदद से गौशालाओं की ठेल (वह टंकी जिसमें गोवंश मुंह डालकर पानी पीते हैं) को पानी से हमेशा भरा रखा जा सके।

अमोल कुमार जिंदानी, संयोजक, भक्त मंडल

गौशाला की करो मदद इनकम टैक्स पाओ छूट

» जिले में होगा गौ संरक्षण, दूध से मिलेगा पोषण

» गोबर से खेती के लिए कम्पोस्ट खाद भी मिलेगी

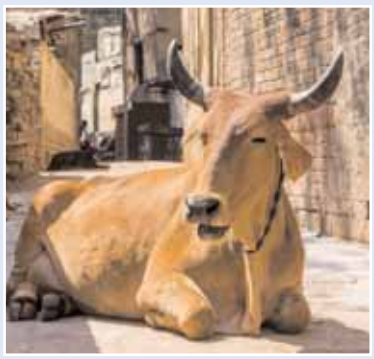

इंदौर। मुख्यमंत्री गौसेवा योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश सरकार द्वारा समस्त गाय प्रेमियों को गायों के संरक्षण और गौ सेवा से जोड़ने के लिए एक अभियान चलाया गया है। सभी नागरिकों को शासन के गौ संरक्षण और गौसेवा अभियान में जोड़ने के लिए गौपालन बोर्ड का पोर्टल बनाया गया है। कोई भी व्यक्ति जो गौ सेवा या संरक्षण के इच्छुक हैं वे मध्यप्रदेश गौपालन बोर्ड के इस पोर्टल पर जाकर सीधे किसी भी गौशाला को आर्थिक सहयोग प्रदान कर सकते हैं। लोगों द्वारा किए गए आर्थिक सहयोग पर इनकम टैक्स की धारा-80 जी की छूट का प्रावधान होगा।

इसके अलावा गौशाला में स्थायी संरचना बनाने जैसे बोरवेल, शेड, बायोगैस निर्माण और पशु आहार के लिए भी दान दिया जा सकता है। यह दान अपने किसी निकटस्थ रिश्तेदार या परिजन की याद में उसकी पुण्यतिथि के अवसर पर या घर में बच्चों के जन्मदिवस या परिवार में शादी की सालगिरह जैसे खुशी के अवसरों पर भी दिया जा सकता है। गौ सेवा और गौ संरक्षण के लिए सरकार द्वारा प्रदेश में कई गौ शालाएं भी शुरू की गई हैं। इनके संचालन के लिए स्थानीय लोगों के अलावा स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद भी ली जा रही है। गौ शालाओं के संचालन और रखरखाव के लिए समाज का सहयोग भी जरूरी है। इसी उद्देश्य से सरकार ने दान में छूट का प्रावधान किया है। गौ शालाओं के जरिए गौ रक्षा तो होगी ही, दूध से पोषण और गोबर से खेती के लिए जरूरी कम्पोस्ट खाद भी मिलेगी।

मुरैना में पैसे के अभाव में अधूरी पड़ी गौशाला कलेक्टर ने निर्माण पूरा करने के दिए निर्देश

■ जनपद पंचायत ने नहीं किया राशि का भुगतान

संवाददाता, मुरैना/पहाड़गढ़

ग्राम पंचायतों को मनरेगा का पैसा अभी तक नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से पंचायतों के निर्माण कार्य अधूरे रह गए हैं। ऐसे ही अधूरे निर्माण में शामिल हैं, धौंधा पंचायत की गौशाला। जिसके निर्माण पिछले लंबे समय से अधूरा पड़ा है, लेकिन मजदूरी और मटेरियल का भुगतान न किए जाने की वजह से इसका निर्माण पूरा नहीं हो पा रहा है। खास बात यह है कि इस गौशाला के निर्माण को मार्च तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश कलेक्टर ने गौशाला का निरीक्षण करते हुए दिए, लेकिन जनपद पंचायत के जिम्मेदार अधिकारियों ने इसे भी ताक पर रख दिया। अभी तक एक पैसे का भी भुगतान नहीं किया गया है। जिससे गौशाला का निर्माण पूरा नहीं हो पा रहा है। गौरतलब है कि धौंधा पंचायत में गौशाला का निर्माण कराया जा रहा है। पैसा न मिलने से यह काम बीच में ही रुक गया। एक महीने पहले कलेक्टर बी कार्तिकेयन धौंधा पंचायत पहुंचे थे। तब अधूरी पड़ी गौशाला के निर्माण की स्थिति को जाना था। तभी उन्हें यह भी बताया गया था कि राशि के अभाव में काम बंद हो गया है। जिस पर कलेक्टर ने मार्च तक इसका निर्माण हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए थे। गौशाला में पिलर खड़े हो चुके हैं और दीवारें भी कुछ खड़ी हो गई हैं। इसके बाद काम आगे नहीं बढ़ सका। कलेक्टर के निर्देश मिलते ही सरपंच ने निर्माण की प्रक्रिया को तेज कर दिया। लेकिन इसके बावजूद एक भी पैसे का भुगतान नहीं किया गया। जिससे अब यह काम फिर से बंद हो गया है। जबकि निर्देशासनुसार मार्च तक इसको पूरा किया जाना चाहिए था।

सरपंच काट रहे चक्कर

यहां पंचायतों में निर्माणों की राशि का लंबे समय से भुगतान नहीं किया गया है। जिसके चलते सरपंच जनपद के चक्कर काट रहे हैं। धौंधा सरपंच ने भी यहां कई बार पैसा दिए जाने की मांग की। लेकिन निर्माण के लिए पैसा नहीं दिया गया। जिससे यह अभी तक पूरा नहीं हो सका है। जबकि कलेक्टर ने निर्माण कार्य को हर हाल में पूरा करने की बात कही गई थी।

इनका कहना है

कुछ ग्राम पंचायतों के भुगतान शेष हैं। कुछ का कर चुके हैं। जल्द ही सभी पंचायतों को भुगतान कर दिया जाएगा।

■ **आरके गौड,** सीईओ, जनपद पंचायत पहाड़गढ़

मुरैना आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र ने किया कमाल

सरसों के साथ बरसीम की बोवनी किसानों की आय दोगुनी

अवधेश डंडोतिया, मुरैना

सरकारें खेती से किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य पर सालों से काम कर रही हैं, लेकिन मुरैना के आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र ने सरसों की खेती से किसानों की इनकम दोगुनी करके भी बता दी है। इसके लिए सरसों के खेतों में बरसीम के बीज की बोवनी कराई गई। पिछले तीन साल से सरसों के साथ बरसीम बीज की खेती करने वाले किसानों ने केवल सरसों की खेती करने वालों से लगभग दोगुनी आय की। इसलिए इस बार ऐसे किसानों की संख्या बढ़ गई है। मुरैना आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र ने पहले तो अपने अनुसंधान वाली जमीन पर सरसों के साथ बरसीम की खेती का प्रयोग किया।

दोनों फसलों की पैदावार के परिणाम अच्छे आने के बाद, कृषि अनुसंधान केंद्र ने किसान फर्स्ट योजना के तहत जिले के हड़बांसी, साटा, बरौली और लालबांस गांव के किसानों के खेतों में सरसों के साथ बरसीम की फसल भी करवाई। इन गांवों के किसान बीते तीन साल से एक खेत में दो फसलें ले रहे हैं। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार एक बीघा जमीन में चार से साढ़े चार क्विंटल सरसों निकलती है, जो 4500-5000 रुपए क्विंटल के भाव बिकती है। यानी एक बीघा जमीन में 20 से 22 हजार रुपए की सरसों पैदा होती है। इसी एक बीघा खेत में डेढ़ से दो क्विंटल बरसीम का बीज पैदा होता है, जिसका भाव 13000 रुपए क्विंटल है। यानी एक बीघा में 18 से 26 हजार तक का बरसीम बीज पैदा हो जाता है।

बरसीम मुनाफे की खेती

बरसीम बीज की खेती के लिए कोई अलग जमीन नहीं चाहिए, किसानों को अतिरिक्त जुताई का खर्च नहीं उठाना पड़ता। बस एक बीघा में 20 से 25 किलो यूरिया और सरसों की कटाई के बाद एक सिंचाई की जरूरत होती है। इस अतिरिक्त खर्च में सरसों के खेतों में सरसों से ज्यादा बरसीम बीज की खेती से आय होती है।

बरसीम के बीजों की खेती

सरसों के पौधे की लंबाई पांच फीट या इससे ज्यादा भी हो जाती है और बरसीम का पौधा डेढ़ से दो फीट लंबा ही होता है। सरसों के बीज की बोवनी दूर-दूर होती है। सरसों के पौधे जब एक-एक फीट के हो जाते हैं तब, सिंचाई से पहले इसी खेत में बरसीम का बीज फेंककर (बाजरा की तरह) बोया जाता है। सरसों के पौधे ऊपर बढ़ते जाते हैं और उनके नीचे बरसीम की फसल पनपती रहती है। सरसों की फसल कटने के 20 से 25 दिन बाद बरसीम की फसल कटने पर आ जाती है। सरसों की तरह बरसीम की बालियों से भी दाने निकलते हैं। बरसीम की फसल की एक बार छंटाई होती है, जिससे मवेशियों को हरा चारा निकलता है। इसके बाद बालिया आना शुरू हो जाती हैं।

चना-धना की जुगलंबदी ने कीटों से बचाया

कृषि अनुसंधान केंद्र ने कुछ गांवों में चना के साथ धनियां की फसल किसानों से करवाई है। इसके भी कई लाभ किसानों को हुए हैं। चना की फसल में इल्ली रोग ज्यादा लगता है जो धनिया की खुशबू के कारण नहीं लगा। यानी चना के साथ हुए धना की फसल ने कीटों का प्रकोप खत्म कर दिया। इतना ही नहीं, एक बीघा खेत में 10 से 12 हजार रुपए के धनिया की पैदावार किसानों को हुई है। चने की फसल भी अच्छी है और उससे भी 15 से 18 हजार तक की आय किसानों को प्रति बीघा पर होगी।

इनका कहना है

मुरैना जिले में अधिकांश किसान अकेली सरसों की फसल करते हैं। हमने पायलट प्रोजेक्ट के तहत पिछले साल चार गांवों में सरसों के साथ बरसीम की खेती करवाई, जिससे किसानों की आय दोगुनी हुई। इस साल भी इन गांवों में सरसों के साथ बरसीम बीज की खेती हो रही है। इस फसल में कोई अतिरिक्त मेहनत या जमीन नहीं लगती, यह किसानों के लिए अच्छी बात है। बरसीम बीज की मांग भी बहुत है, इसलिए ऊंचे दामों में बिकता है।

डॉ. संदीप सिंह तोमर, वैज्ञानिक, कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना

तीन परियोजनाओं से बदलेगा बीहड़ के किसानों का भविष्य

चंबल अंचल के अन्नदाता होंगे आत्मनिर्भर

संवाददाता, भोपाल

मध्यप्रदेश का ग्वालियर-चंबल वह इलाका जहां पर कभी बंदूकों की गोलियों की आवाजें गूंजा करती थीं, लेकिन अब हरी भरी फसलों से लहलहाएगा। इसकी वजह है प्रदेश की शिवराज सरकार इस अंचल की तीन बड़ी परियोजनाओं पर काम किया जाना। यह तीनों ही परियोजनाएं अलग-अलग आकार वाली हैं। सरकार इन योजनाओं के जरिए इस इलाके की डेढ़ लाख हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने की मंशा जाहिर की है। इन परियोजनाओं के लिए सिंचाई विभाग द्वारा खाका तैयार करने का काम तेजी से किया जा रहा है। खास बात यह है यह तीनों ही परियोजनाएं करोड़ों रुपए की लागत वाली हैं। इनमें पहली परियोजना श्योपुर जिले के पातालगढ़ से होकर बहने वाली पारम नदी पर शुरू की जा रही है। इसके तहत यहां पर तीन सौ करोड़ की लागत से एक बैराज बनाई जानी है। इससे पानी को चंबल कैनाल में भेजा जाएगा। इसकी वजह से अधिक तेजी से पानी टिल एंड तक भेजा जा सकेगा। इसी तरह से भिंड जिले के गोरमी में भी क्वांरी नदी पर प्रस्तावित 350 करोड़ की लागत वाली कनेरा उद्वहन सिंचाई परियोजना से 10 हजार हेक्टेयर में सिचाई का लक्ष्य तय किया गया है।

अनुमति का इंतजारा

सरकार ने भदावर सिंचाई परियोजना नाम दिया है। फिलहाल इन परियोजनाओं के लिए वित्त विभाग से अनुमति का इंतजार है। अनुमति मिलने के बाद टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसी अंचल की तीसरी सिंचाई परियोजना है सिंध नदी पर माधवराव सिंधिया के नाम पर शुरू की जा रही है।

सबसे बड़ी परियोजना

यह तीनों में सबसे बड़ी परियोजना है। इसका निर्माण रतनगढ़ माता मंदिर के समीप किया जाएगा। इससे सवा लाख हेक्टेयर इलाके में सिंचाई होगी। यह सिंचाई भिंड और दतिया जिले के इलाकों में होगी। यह परियोजना विभाग की सबसे अधिक प्राथमिकता में शामिल है। इन तीनों परियोजनाओं से ग्वालियर चंबल अंचल का अधिकांश इलाका हराभरा हो जाएगा।

बीड़ी के स्वदेशी कुटीर उद्योग पर लग जाएगा ताला

देश के 80 लाख लोगों की आजीविका पर संकट!

चार राज्यों की महिलाओं ने कानून के खिलाफ खोला मोर्चा

संवाददाता, भोपाल

मोदी सरकार द्वारा एक कानून में किए गए संशोधन से मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों के सबसे बड़े स्वदेशी कुटीर उद्योग पर ताला डलने की नौबत आ गई है। इसकी वजह से इस उद्योग के माध्यम से रोजी रोटी कमाने वाले करोड़ों लोगों के सामने बड़ा संकट खड़ा होता नजर आ रहा है। यही वजह है कि अब बीड़ी उद्योग से जुड़ी महिलाओं ने विरोध में मोर्चा खोलना भी शुरू कर दिया है। विरोध के मामले में बिहार, झारखंड, कर्नाटक और तमिलनाडु की 44000 महिला बीड़ी मजदूरों ने रैलियां निकालकर किए गए कठोर प्रावधानों को वापस लेने की मांग की है। दरअसल, सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स (विज्ञापन के प्रतिबंध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन) एक्ट, 2003 में केन्द्र द्वारा संशोधन कर कई नए

कड़े संशोधन प्रस्तावित किए हैं। गौरतलब है कि मध्यप्रदेश में सबसे ज्यादा बीड़ी बुंदेलखंड में बनाई जाती है। देश में बुंदेलखंड की पहचान सूखे क्षेत्र से होती है।

आजीविका पर खतरा

बीड़ी बनाने का काम करने वाली महिलाओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रस्तावित संशोधनों से बीड़ी को अलग करने की मांग की जा रही है। खास बात यह है कि देश में बीड़ी बनाने का काम 80 लाख से अधिक घरेलू लोगों द्वारा किया जाता है, जिसमें 80 फीसदी महिलाएं शामिल हैं। नए प्रस्तावित संशोधनों से इन सबकी आजीविका समाप्त होने का खतरा मंडराने लगा है। नए संशोधन कानून बनने पर 200 साल पुरानी भारत में हाथ से तैयार बीड़ी उद्योग,एक स्वदेशी कुटीर उद्योग का रूप ले चुका है।

भारत कैसे होगा आत्मनिर्भर

इस उद्योग से फिलहाल देशभर में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब तीन करोड़ लोग जुड़े हैं। देश में बहु-पीढ़ियोंवाली महिलाएं घरों में बीड़ियां बनाने का काम करती हैं। इससे उनके समय का सदुपयोग होने के साथ ही आय भी होती है। यदि इसके नए संशोधनों को लागू किया जाता है तो किसी भी अन्य व्यवहार्य रोजगार के उपलब्ध न होने की वजह से इन महिला बीड़ी मजदूरों पर, जो आत्मनिर्भर भारत की प्रतीक मानी जाती हैं, इनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा।

स्वदेशी उद्योग को बचाइए

बीड़ी मजदूरी से जुड़ी महिलाओं का कहना है कि कोटपा 2003 के अंतर्गत बीड़ी के लिए अलग से नियम सरकार तय करे। ताकि इस देश के भीतर के, रोजगार पैदा करने वाले, स्वदेशी उद्योग को बचाया जा सके। गौरतलब है कि बीड़ी के कारोबार से देशभर में 80 लाख मजदूरों, पांच लाख पैकर्स और 40 लाख महिला और आदिवासी तेंदूपत्ता तोड़ने का काम करते हैं। इसी तरह से 75 लाख छोटे रिटेलर्स की आजीविका इसी से चलती है।

- गाय का गोबर बेरोजगारों को देगा रोजगार और रोकेगा पलायन
- फैक्ट्रियां खुलने के बाद गोबर की खरीद का एक तंत्र बन जाएगा
- सिर्फ एक मवेशी के गोबर से किसान हर साल 30 हजार रुपए कमाएंगे
- गोबर से पेंट बनाने की एक फैक्ट्री खोलने में 15 लाख का होगा खर्च
- गांव में रोजगार मिलने से शहरों की तरफ पलायन की समस्या होगी खत्म

रंग लाई 'जागत गांव हमार' की पहल, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मप्र को सुझाया फॉर्मूला

मप्र के हर गांव में लग जाए गोबर पेंट की फैक्ट्री कोई भी किसान नहीं करेगा आत्महत्या

संवाददाता, भोपाल

किसानों को नई तकनीक और नए बाजार के साथ अगर जोड़ा जाए तो फिर देश में उनकी आत्महत्याएं पूरी तरह रोकी जा सकती हैं। आज देश में गोबर से पेंट बनाया जा रहा है, जो बाजार में बिकने वाले ऑइल पेंट के मुकाबले बेहतर और सस्ता है। पेंट के लिए गोबर 4 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदा जा रहा है। अगर मध्यप्रदेश के भी हर गांव में एक गोबर पेंट फैक्ट्री लगाई जाए, तो फिर कोई किसान आत्महत्या क्यों करेगा। यह सुझाव केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मप्र सरकार को हाल ही में भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान दिए। गौरतलब है कि

'जागत गांव हमार' ने अपने 22 फरवरी के अंक में 'मप्र के हर गांव में खुलेगी गोबर से पेंट बनाने की फैक्ट्री' शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। जिसमें बताया गया था कि भारत गांवों का देश है। राष्ट्र पिता महात्मा गांधी ने कहा था-असली भारत गांवों में बसता है। अधिकांश ग्रामवासी किसान होते हैं। गांवो में खेतों के अलावा पशुपालन, मुर्गीपालन, मधुमक्खी पालन जैसे व्यवसाय किए जाते हैं। पशुपालन से किसानों को अतिरिक्त आमदनी होती है और कृषि कार्य में सहायता मिलती है। पशुओं का गोबर खाद का काम करता है। इस लक्ष्य को लेकर मप्र को आत्मनिर्भर बनाने की कवायद में जुटी शिवराज सरकार जल्द ही केंद्र से अदेश मिलते ही एक और अनोखी पहले करने की तैयारी में नजर आ रही है। सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो मप्र के सभी 52 जिलों, 293 नगर परिषद, 22,812 ग्राम पंचायत , 313 जनपद पंचायत में गोबर से पेंट बनाने की फैक्ट्री खोली जाएंगी। इससे जहां एक ओर मप्र के किसानों की आय बढ़ेगी, वहीं दूसरी ओर गौ-संरक्षण को भी बढ़ा मिलेगा।

- दुबई और बंग्लादेश नहीं जाएगा संतरा
- पैदावार में 90 फीसदी की कमी

शाजापुर में चौपट हुआ संतरे का 500 करोड़ का व्यापार

अमजद खान, शाजापुर

दिल्ली, मुंबई, जयपुर, चडीगढ़ से लेकर बाग्लांदेश और दुबई में पसंद किए जाने वाले मप्र के शाजापुर के संतरे इस बार इंपोर्ट-एक्सपोर्ट नहीं हो पाएंगे। इस बार यहां संतरे की पैदावार पूरी तरह चौपट हो गई है। पौधों पर फल न लगने से संतरे की पैदावार 90 फीसदी से ज्यादा प्रभावित हो गई है। इसका कारण शुरुआत में पर्याप्त पानी न गिरने और मिस्सी की बीमारी बताया जा रहा है। अपनी खास क्वालिटी और बंपर पैदावार के चलते शाजापुर जिले के संतरे विदेशों में भी भेजे जाते हैं। इनका यहां हर साल 500 करोड़ से ज्यादा का कारोबार होता है। यहां के हजारों किसानों की आजीविका का अहम साधन भी ये संतरे ही हैं, लेकिन, एक बार फिर मौसम

के बदले मिजाज ने किसानों की कमर तोड़ दी।

किसानों को टूटी कमर : संतरे की फसल के लिए मौसम की अनुकूलता अहम रोल अदा करती है। लेकिन, इस बार तय समय पर पर्याप्त बारिश न होने से इन पौधों पर फलन ही नहीं हो पाया। कुछ बागीचों में काली मिस्सी की बीमारी ने रही-सही कसर पूरी कर दी। किसानों की मानें तो तय वक्त पर बारिश और उसके बाद 'तान' यानी पानी की गेप होना फल को विकसित करने में मददगार होता है। लेकिन इस बार तय वक्त पर पर्याप्त पानी न मिलने से पौधों पर संतरे ही नहीं उग पाए।

90 फीसदी से ज्यादा की फसल खराब: शाजापुर जिले में 12 हजार 600 हेक्टेयर में संतरे की खेती होती है। कृषि और उद्यानिकी विभाग से जुड़े वैज्ञानिक भी मानते हैं कि यहां का अनुकूल मौसम संतरे कि बंपर पैदावार देता है। लेकिन, इस बार बारीश के तय समय पर न होने से संतरे कि पैदावार प्रभावित हुई है और नुकसान 90 फिसदी तक हुआ है। ये नुकसान करोड़ों का है।

इनका कहना

अब बगीचों में लगे यह पौधे हरीयाली तो दे रहे हैं लेकिन इन पर संतरे पूरी तरह गायब हैं। इक्क-दुक्का बगीचों को छोड़ दिया जाए तो पूरे क्षेत्र में यही हालात हैं। इससे पहले से तंगहाली का जीवन जी रहे किसान और मायूस हो गए हैं।

एसएस धाकड़, वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक

कृषि विज्ञान केन्द्र दतिया में गेहूं प्रक्षेत्र दिवस का आयोजन

दतिया। कृषि विज्ञान केंद्र, दतिया द्वारा ग्राम सनौरा में गेहूं प्रक्षेत्र दिवस का आयोजन किया गया। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में कृषक स्थाई समिति की अध्यक्ष क्रांती राय उपस्थित रहीं। उन्होंने कहा कि किसान कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा जो भी नवीन तकनीकियां दे रहे हैं उसका पूरा प्रयोग करें और अपनी आय को बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि कृषि विज्ञान केन्द्र जिले में कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। जिसका लाभ कृषि क्षेत्र में स्पष्ट देखा जा सकता है। वैज्ञानिक डॉ. एके सिंह ने कृषकों को बताया कि किसान भाई समय से बोवनी जरूर करें। देर से करने पर उपज पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। केन्द्र द्वारा कृषकों को गेहूं की प्रजाति आरव्हीडब्ल्यू 4106 कृषकों को प्रदर्शन के लिए दी गई थी। उसको सीधे बाजार में न बेच कर अपने गांव व आसपास के कृषकों को दें। जिससे नई प्रजाति का व्यापक प्रसार प्रचार हो सके व अन्य कृषक भी लाभांवित हो सके। वैज्ञानिक डॉ. राजीव सिंह चौहान ने कृषकों को गर्मी की गहरी जुताई के लाभ के बारे में जानकारी दी एवं गेहूं कटने के उपरांत गर्मी की मूंग लगाने की समझाइश दी।

- गोबर के वंदनवार व अगरवत्ती बनाने का सिखाया हुनर
- महिलाएं बोलीं : गांव से साथ देश को बनाएंगे आत्मनिर्भर

गांवों में आत्मनिर्भरता की अलख जगा रहा शारदा विहार

संवाददाता, भोपाल

शिक्षा के साथ गौपालन को लेकर देशभर में आकर्षण के केंद्र शारदा विहार कौशल विकास केंद्र भोपाल इन दिनों एक फिर चर्चा में है। दरअसल, शारदा विहार द्वारा आस-पास के गांवों में स्वावलंबन से स्वरोजगार 'समर्थ' कौशल विकास केंद्र ने हाल ही में एक प्रशिक्षण के जरिए लोगों को आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया है। हालांकि यहां यह पहला अवसर नहीं है, बल्कि इससे पहले भी इस तरह के हुनर जरूरतमंद लोगों के सिखाए जा चुके हैं। प्रशिक्षण के पहले दिन मुगालिया छाप से दो दर्जन से ज्यादा महिलाएं आईं और प्रशिक्षण में भाग लिया। इस दौरान उन्हें हर्बल साबुन बनाने और उप्टन बनाने के साथ ही गोबर से दरवाजों पर लगाए जाने वाले वंदनवार बनाने का हुनर सिखाया गया। वहीं प्रशिक्षण से उत्साहित गांवों से आई महिलाओं ने संकल्प लिया हम भी यह काम करेंगे और गांव के लोगों को भी इस काम के लिए प्रेरित करेंगे ताकि हम हमारा गांव समाज और देश आत्मनिर्भर बने।

यह रहे मौजूद: प्रशिक्षण कार्यक्रम में शारदा विहार के प्रबंधक अजय शिवहरे, समिति की सदस्य उमा शर्मा प्रतिभा शुक्ला, प्रशिक्षण प्रमुख प्रकाश मंडलोई, सहयोगी राकेश डोनी और संस्कार केंद्र के प्रमुख मुकेश चंद्रवंशी व उत्कर्ष बाजपेयी शामिल रहे।

इनका कहना है

दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में दो दर्जन से ज्यादा महिलाओं ने बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया। प्रशिक्षण में गोबर से बनाए जाने वाले दरवाजों पर वंदनवार और अगरवत्ती बनाने का हुनर सिखाया गया ताकि वे अपने घरों में आसानी से स्वरोजगार स्थापित कर सकें। हमारा उद्देश्य है कि गांव में गोबर से अधिक-अधिक गौ शिल्पी बनें। गांवों में गाय का गोबर आसानी से मिल जाता है। इसलिए गौ शिल्पी पर भी मातृ शक्ति का ज्यादा ध्यान है।

प्रकाश मंडलोई, प्रशिक्षण प्रमुख, शारदा विहार

आवश्यकता

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर और मुरैना से प्रकाशित

जागत गांव हमार

कृषि और पंचायत पर आधारित साप्ताहिक समाचार पत्र के लिए जिला, जनपद स्तर पर संवाददाता चाहिए।

संपर्क करें

जबलपुर, प्रवीण नामदेव-9300034195
शहडोल, गोपाल दास बंसल-9131886277
नरसिंहपुर, प्रहलाद कौरव-9926569304
हरदा, राजेन्द्र बिल्लोरे-9425643410
विदिशा, अवधेश दुबे- 9425148554
सागर, अनिल दुबे-9826021098
दमोह, बंटी शर्मा -9131821040
टीकमगढ़, नीरज जैन -9893583522
राजगढ़, गजराज सिंह मीणा -9981462161
मुरैना, अवधेश दण्डोतिया -9425128418
शिवपुरी, खेमराज मौर्य-9425762414
भिण्ड- नीरज शर्मा-9826266571
खरगौन, संजय शर्मा-7694897272
सतना, दीपक गौतम-9923800013
रीवा-धनंजय तिवारी-9425080670
रतलाम, अमित निगम-70007141120
झाबुआ-नोमान खान-8770736925

कार्यालय का पता:- लाजपत भवन प्रथम तल, आईसीआईसीआई बैंक के पास, एमपी नगर, जोन-1, भोपाल, मप्र,
संपर्क करें- 07554064144, 9229497393, 9425048589

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादकः अजय कुमार द्विवेदी, संपर्क-9229497393, 9425048589, ईमेलः- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)